SN (4)

ECONOMICS

BA Part II Hons Paper IV

PUBLIC FINANCE

Ques → भारत जैसे विकासशील देशों में लोक वित्त का महत्व दर्शाइये ? (Importance of Public Finance in developing Economy)

Ans → प्रत्येक देश का आर्थिक जीवन सार्वजनिक या लोक वित्त से प्रभावित होता है क्योंकि लोक वित्त कि क्रिया कलाप लोगो के अधिकतम सामाजिक एवं आर्थिक लाभ में सक्रिय योगदान देते है। यह साधारणतया सर्वांगीण विकास के लिए अधिक उत्पादन एवं उचित वितरण द्वारा समानता का अवसर प्रदान करता है। सार्वजनिक वित्त की क्रिया कलाप जैसे ग्रान्ट एवं सब्सिडियाँ कराधान, सार्वजनिक ऋण एवं सुनियोजित व्यय व्यवस्था अधिक उत्पादन एवं उचित वितरण में सहायक सिद्ध होती है। लोक व्यवस्था विकसित एवं विकासशील देशो में आर्थिक विकास, बचत एवं निवेश में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता एवं धन के समान वितरण में सहायक होती है।

भारत जैसे विकासशील देशो की समस्या विकसित देशो से भिन्न होती है। विकासशील देशो की समस्या है कि वे प्रभावपूर्ण मात्रा माँग को बनाकर आर्थिक वृद्धि दर मे स्थिरता बनाये रखें तथा लोगो में बचत दर को कम करके उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ायें किन्तु विकासशील देशो में पूँजी निर्माण को बढ़ाने के लिए बचत बढ़ाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इन देशो के समक्ष सदैव ही कम आय एवं ऊँचे उपभोग दर की समस्या रहती है। अतः इस कुचक्र को तोडने के लिए लोक व्यवस्था ही महत्व पूर्ण सिद्ध हो सकती है। संक्षेप मे लोक व्यवस्था भारत जैसे विकासशील देशो में निम्नप्रकार महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

(1) बचत एवं निवेश को बढाना → विकासशील देशो में आर्थिक विकास के लिए पूँजी निर्माण की आवश्यकता होती है जो बचत एवं निवेश में वृद्धि करके ही सम्भव है। अल्पविकसित

PTO

एवं विकासशील देशो में बचत एवं निवेश की दर कम होती है तो वहाँ उपभोग की प्रवृति ऊँची होती है। जनसंख्या वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा इन देशो में बचत का बहुत बड़ा हिस्सा अनुत्पादक मदों पर खर्च किया जाता है। इन अनुत्पादक मदों के उपभोग रोकने के लिए ऊँचा कर लगाना चाहिए व्यक्ति आय एवं निगम आय पर भी कर लगाये जाने चाहिए करारोपण ही ऐसा प्रभावशाली माध्यम है जिससे निजी उपभोग एवं निवेश को घटाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है।

(2) पूँजी निर्माण (Capital Formation) आर्थिक विकास को द्रुत गति प्रदान करने के लिए पूँजी निर्माण को बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि विकासशील देशो में पूँजी निर्माण की गति धीमी होती है। जिसे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली एवं सुनियोजित करारोपण नीति की आवश्यकता होती है। इस सम्बंध मे डा० राजलीत सिंह का कथन ठीक प्रतीत होता है कि " एक ~~अल्पविकसित~~ अल्पविकसित देश में ~~प्रारम्भिक~~ आरम्भिक स्थितियो में सभी आर्थिक नीतियाँ और उपाय आवश्यक रूप में उत्पादन पर केन्द्रित होने चाहिए तथा राजकोषीय नीति पूँजी निर्माण के उपकरण के रूप में कार्य करे।" इस प्रकार सार्वजनिक वित्त का सर्वप्रथम तथा परम लक्ष्य है पूँजी निर्माण का संवर्धन करना। इस सर्दंभ मे आर नर्क्स का कहना है कि " आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक वित्त का लक्ष्य आय के असमानताओ में कमी लाना नहीं है परन्तु इसका लक्ष्य आय के उस अनुपात को बढ़ाना है जो पूँजी निर्माण को जाता है।

(3) नियोजित आर्थिक विकास (Planned economic development) — अल्पविकसित एवं विकासशील देशो में उत्पादक साधन मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप में सीमित होते है. उनका अनुकूलतम एवं योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाना आवश्यक है। नियोजित आर्थिक विकास सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था से ही संभव हो सकता है। योजनाबन्दी की

संपूर्ण मशीनरी सार्वजनिक वित्त के क्षेत्रवाद के द्वारा कार्य करती है। सार्वजनिक वित्त के नियम तीव्र आर्थिक विकास की योजनाबद्धी में सहायक होते हैं।

(4) → साधनों का अनुकूलतम उपयोग (optimum utilization of resources) → अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में दुर्लभ एवं सीमित साधनों का दुरुपयोग होता है, क्योंकि इन देशों में राजकोषीय एवं मौद्रिक व्यवस्था निर्बल एवं दोषपूर्ण होती है। साधनों का अनुकूलतम उपयोग न करना इन देशों की गंभीर समस्या है। इस समस्या का हल उचित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति में निहित है।

(5) धन एवं आय का समान वितरण सुनिश्चित करना (To secure equal distribution of wealth and income) विकासशील देशों में धन एवं आय का वितरण बहुत असमान है। इन देशों में अमीर लोग अधिक अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और अधिक गरीब। आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। यह स्थिति इन देशों के विकास में बहुत बड़ी अवरोधक है। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील कर नीति अपनानी चाहिए इसके अलावा ~~विकासशील~~ विलासिता संबंधी वस्तुओं पर बड़ी मात्रा में कर लगानी चाहिए तथा आवश्यक उपभोग वस्तुओं को कर से छूट दी जानी चाहिए। सरकार को उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाना चाहिए। निर्धनों को वस्तुओं एवं आवश्यक सुविधा उपलब्ध कर उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके ही आय के असमानताओं में कमी लायी जा सकती है।

(6) मुद्रा स्फीति को रोकना (To counterfeit inflation) भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक विकास के साथ मुद्रा स्फीति की एक गंभीर समस्या है। इन में मुद्रा की पूर्ति लोच बेलोचदार होती है जबकि वस्तुओं की मांग लोचदार होती है जिसके कारण अर्थव्यवस्था में जो व्यय किया जाता है उससे उत्पादन कम मात्रा में बढ़ता है जबकि

PTO

मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ने के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा स्फीति में वृद्धि होने से देश में आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक समस्या उत्पन्न हो जाती है अतः इस समस्या का निदान आवश्यक हो जाता है। मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कर दरों में वृद्धि की जानी चाहिए तथा प्रदर्शन एवं विलासी वस्तुओं पर भी कर वृद्धि कर दी जानी चाहिए इसके अलावा इन उत्पादक वस्तुओं पर अधिक निवेश किया जाना चाहिए जिनसे शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हो सके।

(7) लोगों का आर्थिक जीवन (Economic life of the people) लोगों के आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए सरकार लोगों पर कर लगाती है तथा व्यय करती है। सरकार साधारण लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एवं कल्याण के लिए व्यय करती है तथा दूसरी तरफ उच्च आय पर कर लगाती है। इसके अलावा विलासी एवं नशीली वस्तुओं पर उच्च कर लगाकर उनके प्रयोग पर रोक लगाती है। कर से प्राप्त आय निर्धन वर्ग पर खर्च करके सरकार आर्थिक असमानताओं में कमी लाने का प्रयास करती है। निर्माण कार्यों पर व्यय करके सरकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार का सृजन करती है।

(8) पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक वृद्धि (Full employment and Economic growth) — आधुनिक युग में सरकार कल्याणकारी राज्य का कार्य करती है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उत्पादन एवं रोजगार के अवसर बढ़ाती है अल्पविकसित देशों में निम्न उत्पादन एवं रोजगार की समस्या होती है। अतः राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार उत्पादन एवं रोजगार का सृजन कर सकती है। राष्ट्र की आर्थिक नीतियां पूर्ण रोजगार तथा तीव्र आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होती है।

(9) आर्थिक असमानताओं में कमी → विकासशील देशों में आर्थिक विषमता पायी जाती है जिसको घटाये बिना कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए सरकार उच्च आय वर्ग पर उच्च दर से कर लगा सकती है तथा दूसरी तरफ निर्धन वर्ग के कल्याणकारी सुविधाओं में खर्च कर सकती है। इस सम्बंध में प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाना उचित है। शीघ्र प्रतिफल देने वाली योजनाओं में व्यय करके देश में उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाया जा सकता है।

समाप्त

N. Ram